शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

भारत में मानव संसाधन एवं वैश्वीकरण का प्रभाव

डॉ.अमिताभ पाण्डे
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

मानव संसाधन नियोजन का लक्ष्य मानव शक्ति के अपव्यय को रोककर उसका प्रभावशाली और अधिकतम उपयोग करना होता है। भारत में मानवीय श्रम का बाहुल्य मानव संसाधन नियोजन को आवश्यक बना देता है। भारत जैसे विकासशील देश में निरंतर बढती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रशिक्षित, सही व्यक्ति की खोज की आवश्यकता बढ गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में मानव संसाधन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

गोरडन मेकबेथ के अनुसार 'मानव संसाधन नियोजन में दो चरण सम्मिलित हैं, प्रथम चरण मानव संसाधन आवश्यकताओं का नियोजन तथा द्वितीय चरण 'मानव संसाधन की पूर्ति का नियोजन'।

प्रगतिशील राष्ट्र अपनी मानवशक्ति आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं तथा दीर्घकाल में बदली हुई परिस्थिति में आवश्यक संशोधन करते रहते हैं।

वर्तमान वैश्विक वातावरण में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। भारत की जनसंख्या का एक बडा हिस्सा उत्पादक समूहों में है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख योजना है। इसमें 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जायेगा। भारत की गणना दुनिया के उन देशों में की जाती है जहां 25 वर्ष से कम लोगों की कुल आबादी 54 प्रतिशत से अधिक है। हमारे युवाओं को इक्कीसवी शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और नौकरियों के लायक बनाना चाहिए। हमारे यहां काम करने लायक 5 प्रतिशत से भी कम लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिलता है, जिससे वे नौकरी के लायक बन सकें। इस उद्देश्य से स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे कारोबारियों को अर्थव्यवस्था की बडी शक्ति बनाते हुए कहा कि, उन्हें वित्तीय सहयोग देने के लिए बैंकों को बडे दिल के साथ ज्यादा संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। सभी बैंक छोटे-छोटे कारोबारियों की मदद करें। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को यही लोग चलाते हैं। छोटे कारोबारियों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुद्रा बैंक योजना

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

(माइक्रो यूनिट्स डेव्हलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी) के तहत करीब 66 लाख लोगों को 42 हजार करोड मिले हैं। इसके लाभार्थियों में 24 लाख केवल महिलाएँ हैं। मुम्बई के शैलेष भोंसले को मुद्रा योजना के तहत 8 लाख कर्ज मिला है। इससे उन्होंने सीवेज ड्रेस और सफाई का कारोबार शुरू किया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने स्वच्छता अभियान के संबंध में कहा था कि यह नये उद्यमी तैयार करेगा। इस हेतु 20000 करोड रूपये का कोष निर्धारित किया गया था और इसमें 3000 रू ऋण गारंटी राशि की घोषणा की गई है।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री नेहरूजी ने किया था वहीं मोदी जी न्यूनतम शासन के अपने आग्रह के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। नेहरू एक आधुनिक भारत का निर्माण इस्पात के कारखानों, भारी उद्योग बिजली निर्माण की इकाईयां, बडे बांधों जो सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक देते थे। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र का और अधिक विस्तार किया उन्होनें बैंकिग, बीमा खनन, कोयले का राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बहुत महत्व दिया।

गत छह दशकों में भारत का निजी क्षेत्र एक बेहद प्रतिस्पर्धी और वैश्विक आकार वाले उद्यम के रूप में विकसित हुआ है। यहां तक कि इस्पात एवं भारी उद्योग रूप में पहले सार्वजनिक क्षेत्रों में ही उपक्रम हुआ करते थे। टी एन निनान ने अपनी किताब द टर्न आफ द टोटोइज में दर्ज किया है कि पहले जहां भारत में होने वाला लगभग पचास फीसदी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता था अब यह महज बीस फीसदी तक सिमटकर रह गया है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ताओं का संरक्षण और बीमार इकाइयों में सुधार के उद्देश्यों में असफल रहा है, जिससे बाद की सरकारों ने विनवेश और निजीकरण को बढावा दिया।

यूपीए सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि लाभ कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी सरकार द्वारा की जाये और घाटे में चल रही इकाइयों को बेच दिया जाये। मोदी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। 14वे वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाली इकाइयों को वरियता में ही सरकार की खासी हिस्सेदारी रहेगी।

दिव्य एक्सप्रेस - विचार मंथन विरासत को ढोने की मजबूरी क्यों

सोमवार 30 नवम्बर 2015

वैश्वीकरण का प्रभाव

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया - सरकार की घरेलू रक्षा उद्योग को बढावा देने की नीति बाई इंडियन तथा 'बाई एंड मेक इंडियन' श्रेणीयों का बाई ग्लोबल से पहले स्थान आता है। घरेलू रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश नीति को मंजूरी दी है, जिससे आधुनिकतम एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी साथ-साथ मिलती है। अगले 7-8 वर्षो में हम मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत 130 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करने जा रहे है। साथ ही 25000 करोड रूपये ज्यादा का कारोबार होना है। (मनोहर पर्नीकर रक्षा मंत्री डोग व्यापार पत्रिका अप्रैल 2015)

भारतीय वस्त्र उद्योग - कुछ दशक पहले तक यह उद्योग असंगठित क्षेत्र में विद्यमान था परंतु 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के फलस्वरूप धीरे-धीरे इसने संगठित क्षेत्र का रूप धारण कर लिया है। भारतीय

अर्थव्यवस्था को भारतीय कपडा उद्योग ने विदेशी कंपनियों के लिए खोलने से विश्व में अपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया है। विद्यमान समय में भारत का वस्त्र उद्योग 3.5 करोड लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वस्त्र निर्यात का लक्ष्य 39 अरब अमेरिकी डालर था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	स्थिति	क्षेत्र	2003	विकासकर्ता /प्रमोटर	विवरण
महेन्द्र सिटी (कार्यरत्)	तमिलनाडु	607.1	कपडा एवं फैशन सामग्री	महेन्द्रा समूह एवं तमिलनाडु	महेन्द्र नगर भारत का पहली सघन व्यापार नगर है जो व्यापार एवं जीवन शैली क्षेत्रों मे बड़ा है व्यापार क्षेत्र कार्य क्षेत्र उपलब्ध यह क्षेत्र मुख्यरूप से निर्यात और घरेलू टेरिफ रिया उन कंपनियों के लिए है।
सूरत कपडा पार्क (कार्यरत्)	गुजरात	56	कपड़ा	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	इसमें मुख्य औद्योगिक इकाई जैसे सारी नियत वेनस परिधान बेंचमार्क क्लोथिग पी के इंटरनेशनल फार्मल प्रिंट जी और फैशन और गंगा नियात आदि
ब्रांडिक्स इंडिया सिटी (कार्यरत्)	आन्धप्रदेश	4047.7	कपडा	ब्रांडिक्स इंडिया सिटी प्रा.लि.	यह गहन कपडा आपूर्ति चैन सिटी की योजना है ताकि इस जोनम विश्व श्रेणी की कपडा चैन भागीदारी का स्थापित किया जाए। यहां पर 600 लाख लीटर पानी उपलब्ध है इस क्षेत्र में पानी को साफ करने वाला विश्व स्तर का संयंत्र उपलब्ध है यहां पर 200 मेगावट पावर का सब स्टेशन भी उपलब्ध है।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद् (कार्यरत्)	कर्नाटक		कपडा	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद	

उपयुक्त चार विशेष क्षेत्रों के अलावा 13 को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी है और 19 को औपचारिक रूप से स्वीकृति तथा 12 को अधिसूचित किया गया है। जनवरी 2000 से जून 2011 तक 482 मिलाने तथा अधिग्रहण के

भारतीय वस्त्र उद्योग - महावीर - उद्योग व्यापार पत्रिका अप्रैल 2015
भारतीय अर्थव्यवस्था - प्रतियोगिता दर्पण 2015
विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विवरण तथा उनकी स्थिति

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

मामले शामिल हैं। मामले मिलाने एवं अधिग्रहण की जानकारी निम्नलिखित है :

कंपनी	व्यापार क्षेत्र
वेल्सन इंडिया लिमि.	घरेलू वस्त्र, वाचरोप, टेरी टावल
वर्द्धमान समूह	धागा, कपडा, सिलाई -धागा एक्रलिक फाइबर
आलोक उद्योग लि	घरेलू वस्त्र, वूवन एवं निटिड परिधान, कपडा परिधान और पालिस्टर धागा
रेमण्ड लि	वर्सटेड सूटिंग, रंगीन कपडा, डेनिम, शर्टिग, उनी आउटर वियर
अरविंद मिल्स लि.	कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान उत्पाद, डेनिम
बाम्बे डाईग एवं मेन्युफैक्चरिंग कं.	बेड लिनेन तौलिया फर्निशिंग सूट का
मेन्युफैक्चरिंग कं.लि	कपडा, शर्ट, ड्रेस, सूती और पालिस्टिर साडियाँ
गार्डन सिल्क मिल्स	डाई एवं प्रिंटिड कपडा
मफतलाल इण्डस्ट्री	शर्टिग, पापलिन, बाटम, वियर, कपडा, वायल

आदित्य बिडला नूवो आदित्य बिडला मदुरा परिधान, लाइफस्टाइल मार्केट समूह की कंपनी जिसमें तीन प्रभाग (लाउं, फिलीप, वाने हुसैन, एलीन सोली, क्लेक्टिव) शामिल है

अप्रैल - जनवरी	अप्रैल - जनवरी	अप्रैल - जनवरी	परिवर्तन
तैयार परिधान	3076	3437	11.74
सूती कपडा	2596	2326	10.4
ऊंन एवं ऊनी कपडा रेशम	107	99	7.48
कालीन	229	254	12.39
रेशमी	1.4	11.82	744.29
कुल वस्त्र	7766	7793	0.35
कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग के का प्रतिशत	10.57	10.78	

कपडा उद्योग मे निवेश - कपडा उद्योग मे अप्रैल 2000 से फरवरी 2013 के दौरान 1.22 अरब अमेरिकी डालर का सीधे विदेशी निवेश प्राप्त किया है। भारतीय वस्त्र उद्योग का आकार 2020 तक 220 अरब अमेरिकी डालर तक होने की संभावना है। साथ ही हमारा देश परंपरागत कपडे पहनने की कला में विभिन्न गांवों एवं शहरों में कुटीर उद्योग के रूप में फैला है, जिनमें कुछ विश्व प्रसिद्ध है। यह उद्योग देश में कृषि के पश्चात् सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है।

रेल्वे - वैश्वीकरण के बढते प्रभाव को ध्यान में रखकर रेल्वे का विस्तार आधुनिकीकरण हेतु अगले 5 वर्षो में 8.50 लाख करोड रू के निवेश की योजना है। 2015-16 में लक्षित संचालन अनुपात को 88.5 प्रतिशत करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंधन में नई विधियां अपनाई जायेंगी। आदर्श स्टेशन योजना के तहत 200 और स्टेशनों को शामिल किया जायेगा जिसमें निशुल्क वाई फाई की योजना बेहतर गुणवत्तायुक्त भोजन पानी हेतु जानी मानी एजेंसियां, साफ हेतु नये विभाग की स्थापना का प्रस्ताव, गाडियों की मौजूदा रफ्तार बढाकर 160 से 200 किमी प्रतिघंटा करना रेल्वे मे निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए निजी सरकारी सहभागिता की ईकाई का पुर्नगठन, भारतीय रेल को पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु सी.एन.जी एवं डीजल से चलाने की व्यवस्था सरकार शुरू कर रही है।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सीमेंट उद्योग पर वैश्वीकरण का प्रभाव - 100 स्मार्ट शहरों के विकास इत्यादि की हाल ही की सरकारी पहलों से सीमेंट उद्योग के बहुत तेजी से बढने का अनुमान है। लैफार्ज, हालसिम और वाइक्ट जैसी अनेक विदेशी कंपनियों ने हाल ही में भारत के इन्फ्रास्टक्चर विकास में निवेश किया है। 2000 से सितंबर 2014 के दौरान लगभग 29842.9 लाख अमेरिकी डालर मूल्य का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। भारत में सीमेंट उद्योग की क्षमता 2017 के अंत तक 42.1 टन बढकर होगी।

साख निर्धारक एजेंसी मूडीज ने कहा कि देश में निवेश की स्थिति में सुधार हो रहा है तथा अगले साल मजबूत घरेलू विकास के दम पर भारत वैश्विक दिशा निर्धारित करेगा। एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 20216-17 के अनुसार भारत की विकास दर 7.5 पर रहेगी। इस दौरान विनिर्माण गतिविधियों में उछाल से अगले साल की गैर वित्तीय कंपनियो के विकास को समर्थन मिलेगा। सरकार में सुधार ज्यादा जरूरी (गुरूशरण दास दैनिक भास्कर 2 दिसम्बर 2015)

सरकार में सुधार आर्थिक सुधार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे छोटे उद्यमियों के लिए भारत आकर्षण का केन्द्र बनेगा और देश में नौकरियाँ पैदा करने की जिम्मेवारी है। खासतौर पर निर्माण उद्योग में जो हर देश मे सबसे ज्यादा नौकरियों का निर्माता है। भारत की समस्याएँ राजनैतिक से ज्यादा प्रशासनिक और प्रबंधन से संबंधित है। ऐसे मे प्रधानमंत्री मोदी को पूरा ध्यान रिश्ते ठीक करने पर देना चाहिए। खनन, स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी ऐसे काम का उदाहरण है। जनधन योजना, आधार और मोबाइल बैकिंग के जरिये नगदी के हस्तातंरण से सब्सिडी की कारगर डिलीवरी भी ऐसे ही उदाहरण हैं। हाल ही में एफ.डी.आई का उदारीकरण भी एक अन्य उदाहरण है, जिसने कई क्षेत्रों में आटोमेटिक प्रवेश देकर लालफीताशाही के पर काट दिये हैं। मध्यस्थता व वाणिज्यिक अध्यादेश और दिवालियां कानून का मसौदा भी इसी श्रेणी मे आता है। भविष्य के बाजारों के लिए मानव संसाधन में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री की योजना से एवं वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाकर हमारी अर्थव्यवस्था एक नये युग की शुरूआत करेगी।